यू पी एस सी परीक्षा ने खोली सरकार की पोल

फ़रीदाबाद (म.मो.) यू पी एस सी (संघ लोक सेवा आयोग) ने पहली बार इस शहर में अपने परीक्षा केन्द्र बनाये, वह भी पूरे 38 स्थानों पर। ये सभी स्थान प्राईवेट स्कूल थे। इनमें से केवल दो केन्द्रीय विद्यालयों में थे जो भारत सरकार के आधीन हैं। तंत की बात यह है कि यू पी एस सी ने हरियाणा सरकार के एक भी स्कूल को इस योग्य नहीं पाया कि वहां एक दिन अभ्यार्थियों को बैठाकर उनकी परीक्षा ले सके।

योग्य समझे भी कैसे, एक भी स्कूल तो ऐसा नहीं है जिसकी इमारत सही सलामत हो, जिसमें शौचालय व पीने का पानी हो। कमरों में पंखा लटका है तो बिजली की तार नहीं है, तार भी है तो बिजली कटी पड़ी है। रोशनी के लिये अव्वल तो बल्ब ही नहीं है अगर है तो वह जलता नहीं। यह हालात तो तब हैं जब हुड्डा साहब शिक्षा के इस 'हब' पर सैंकड़ों करोड़ वार्षिक खर्च कर रहे हैं। जाहिर है यह सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ रहा है।

यू पी एस सी की इस प्रतिष्ठित परीक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन के हाथ-पांव पूरी तरह से फूले हुए थे। सप्ताह भर पहले से पूरे प्रशासन में हड़कम्प की स्थिति बनी हुई थी।

दर्जनों विशेष ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तैनात किये गये। पुलिस के विशेष कड़े प्रबन्ध किये गये; मानो परीक्षा न होकर कोई हुड़दंग होने वाला हो। माडर्न स्कूल सेक्टर 17 के बाहर अभ्यार्थियों की लम्बी कतार लगी थी। पूछने पर पता चला कि एक-एक की पूरी जामा तलाशी ली जा रही है। पानी की बोतल तक अन्दर ले जाने से रोकने पर जब एक परीक्षार्थी अड़ गया और पूछने लगा कि दिखाओ कहा है ऐसा कोई आदेश तो उसे जाने दिया। दोपहर बाद वाले पेपर के लिये भीतर जाते वक्त उसी कर्मचारी ने बताया कि ए डी सी साहब ने अब पानी की बोतल अलाउड कर दी है। जबकि दिल्ली, चंडीगढ व अन्य परीक्षा केन्द्रों पर यह सब ड्रामेबाज़ियां नहीं होती।

दरअसल स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों में न तो बेसिक समझ है न प्रशासनिक योग्यता। बस हव्वा खड़ा करके दहशत का माहोल बना कर काम को निकालने की फ़िराक में रहते हैं। ऐसे ही कुछ नालायक लोग परीक्षा कक्षों में परीक्षार्थियों की निगरानी कर रहे थे। इन्हें न तो बोलने की समझ थी न सामान्य ज्ञान।

बाद दोपहर वाले पेपर पर एक परीक्षार्थी ने पेपर का नाम जी.एस.II लिखा तो सुपरवाइज़र ने कहा कि यह तो गलत लिख दिया। पेपर तो सी-सैट का है। परीक्षार्थी ने जब उस पर अंग्रेजी में डांट मारी कि जब तुम्हें पता कुछ नहीं तो डिस्टर्ब क्यों करते हो, तो वह वहां से खिसका। इसी तरह की अनेक छोटी-मोटी घटनायें सुपरवाइज़री स्टाफ़ की सुनने को मिली। एक जगह तो इस स्टाफ़ के ऊंची आवाज में बातें करने से डिस्टर्ब होने पर परीक्षार्थियों को ही सुपरवाइज़रों को धमकाना पड़ा।

एन आई टी का थाना नहीं समझौते की दुकान है

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 27-28 की मध्य रात्रि करीब ग्यारह बजे श्रीमती मंजू चोपड़ा अपने 3 बेटों के साथ एन एच 5 के मकान नंम्बर ए-27 से जगराते के बाद घर लौट रही थी तो थाना एन आई टी के ठीक सामने राजेन्द्र गांधी, विजय गांधी, मनीष गांधी व 5 अन्य ने इनकी माइक्रा कार को घेर कर रोक लिया। इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने उनकी किसी कार में टक्कर मारी है। मां बेटों ने सफ़ाई दी कि वे तो उनकी कार की तरफ़ गये ही नहीं बल्कि ए-27 में (जगराते) से निकल कर आ रहे हैं।

गांधी गिरोह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि वे बाहुबल के नशे में डंडों व रॉडों से लैस थे। मां व बेटों को खींच कर गाड़ी से निकाल लिया और बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया कार को तहस-नहस कर दिया। मां ने काफ़ी गुहार लगाई लेकिन गांधी गिरोह कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। मां, सामने ही स्थित, थाने में दौड़कर गयी।

जब तक वहां से एक पुलिसकर्मी हिलता-डुलता निकल कर आया तब तक गिरोह के सभी लोग फ़रार हो चुके थे केवल एक को मंजू के बेटे ने काबू कर रखा था, जिसके हाथ में रॉड थी। मार-पीट के दौरान मंजू के एक बेटे ने हमलावरों में से एक की रॉड छीन कर अपने बचाव में उन पर वार किये जिससे हमलावरों में से भी एक को मामूली चोट लग गयी।

मौके पर पहुंची पुलिस रॉड वाले हमलावर को थाने ले गयी जिसे करीब एक घंटे बाद छोड़ दिया गया,। मंजू व उसके तीनों बेटों को गंभीर हालत में एस्कार्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन पुलिस ने न तो कोई रपट दर्ज की न ही मेडिकल कराने व बयान लेने अस्पताल गयी। ड्यूटी अफ़सर उपनिरीक्षक सतपाल को बार-बार फोन करने पर उसने राजकुमार नामक हवलदार को बयान लेने अस्पताल भेजा जो सतपाल के दिशा निर्देशन में घायलों के बयान लेने की अपेक्षा नाटकबाज़ी करने लगा। मामले की गम्भीरता को देखते हुए पीड़ित पक्ष ने रात करीब 3 बजे थाने के एस एच ओ भारत भूषण को फ़ोन किया तो उनके कहने पर कहीं जाकर राजकुमार ने बयान दर्ज किये।

उधर उपनिरीक्षक सतपाल से जब भी पीड़ित ने बात करने की कोशिश की तो वह बार-बार कहता कि वह गश्त में है; जबकि हकीकत में वह विपिन हलवाई (5 एम-24) की दुकान में ए.सी. चला कर खरटि भर रहा था और एस एच ओ की सरकारी गाड़ी बाहर खुली खड़ी थी, उसे चाहे जो मर्जी भगा कर ले जाय।

ड्यूटी अफ़सर होने के नाते मामला भी इसी सतपाल के पास था। उसने मामले को गंभीरता से लेकर मुकदमा दर्ज करने के बजाय पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाना शुरू किया कि वह हमलावरों से समझौता कर लें वरना वह दोनों पक्षों पर बराबर का केस बना कर दोनों को बंद हवालात कर देगा। मामला, सुबह होने पर एस एच ओ के सामने लाया गया तो उन्होंने सतपाल को धमकाया तो सही परन्तु उस पर असर कोई खास नहीं हुआ।

शायद यह धमकाना भी एक नाटक ही था। वरना एस एच ओ द्वारा मामूली सी आंख तरेरने पर बिगड़े से बिगड़ा मुलाजिम एकदम सीधा हो जाय, सतपाल की तो औकात ही क्या है।

सारे मामले में गंभीर बात यह है कि थाने के सामने ही लोग कोई वारदात करने से बिल्कुल नहीं घबराते। इसका कारण यही है कि अब थाने, थाने नहीं रह गये, समझौता कराने की दुकानें बन कर रह गये हैं। पुलिस का यही रवैया अपराधियों को अपराध करने के लिये प्रेरित करता है। और इसके लिये असल जिम्मेदार थानों के सुपरवाइजरी अफ़सर हैं।

मोदी बनवायेंगे सड़क जनता से होगी वसूली कड़क

कैथल (म.मो.) दिनांक 19 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने यहां एक विशाल जनसभा करके 1393 करोड़ की लागत से बनने वाले सड़क प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। 166 किलो मीटर लम्बी यह सड़क राजस्थान के राजगढ को हिसार, बरवाला, नरवाना के रास्ते कैथल से जोड़ेगी।

दरअसल सड़क तो पहले से ही मौजूद है। आज से नहीं सैंकड़ों साल से है। समय परिवर्तन के साथ-साथ इस सड़क की शक्लो-सूरत में भी परिवर्तन होता रहा है। कभी यह बिल्कुल कच्ची थी, जिस पर बैल व ऊंट गाड़ियां चला करती थी। ज्यों-ज्यों यातायात के साधन उन्नत होते गये व उनकी संख्या बढती गयी, सड़क भी उन्नत यानी मजबूत व चौड़ी होती गयी। लेकिन किसी भी राज में इस सड़क को बेचा नहीं गया था। हर राज में राजकोष से ही इसका निर्माण एवं रखरखाव होता रहा। परन्तु 1998 में आई भाजपा की वाजपेयी सरकार ने सड़कों के निर्माण के नाम पर सड़कों को बेचने का धंधा शुरू कर दिया जो बाद में कांग्रेस राज को भी काफ़ी रास आया।

उसी परिपाटी को आगे बढाते हुए अब मोदी सरकार ने इस सड़क को भी बेचने का निर्णय लिया है। वैसे बकौल मुख्यमंत्री हुड्डा यह निर्णय तो उनकी (कांग्रेसी केन्द्र) सरकार ने ही ले लिया था, बस काम शुरू नहीं करा पाये थे। दूसरे शब्दों में किसी कम्पनी से लेन-देन की डील फ़ाइनल नहीं हो पाई थी। वह कसर बस अब मोदी जी के गडकरी व कृष्णपाल पूरी कर देंगे। डेढ साल में सड़क बनाने का दावा तो पता नहीं कब पूरा होगा लेकिन वाहनों से टोल-टैक्स वसूली बहुत जल्दी यानी उसी दिन से शुरू हो जायेगी जिस दिन मोदी सरकार की किसी कम्पनी से डील फ़ाइनल हो जायेगी। कम से कम 4 स्थानों पर टोल वसूली की जायेगी और फ़िर वही जनता जो आज मोदी-मोदी कर रही है टोल देते वक्त वैसे ही बिलबिलायेगी जैसे रोहतक-पानीपत व रोहतक-रिवाड़ी सड़क पर बिलबिला रही है। विदित है कि सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव के लिये प्रत्येक वाहन, दुपहिया से लेकर भारी से भारी वाहन से अच्छा-खासा रोड टैक्स वसूला जाता है। पहले यह टैक्स तिमाही एवं वार्षिक आधार पर वसूला जाता था जो कि आजकल 15 साल का एकमुश्त ही वसूल लिया जाता है। इसके अलावा यात्री कर, गुडस टैक्स, परमिट फ़ीस इत्यादि के नाम पर अलग से वसूला जाता है। इसी वसूली से अब तक सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव का काम चलता आ रहा था। लेकिन जब घूसखोरी बढने लगी तो टैक्स की रकम कम पड़ने लगी। घूसखोरी से निपटने के बजाय, करीब 35 वर्ष पूर्व पैट्रोल व डीज़ल पर भी रोड सैस लगा दिया गया। भस्मासुर सी बढती घूसखोरी जब इसे भी निगल गयी तो सड़कें बेचने व टोल टैक्स लगाने की प्रक्रिया शुरू की गयी।

भीतर की जानकारी रखने वाले बताते हैं कि वसूले गये टोल-टैक्स का मात्र एक चौथाई सड़कों पर, एक चौथाई नेताओं व अफ़सरों की जेब में तथा शेष ठेकेदार कम्पनी के जेब में जाता है। जेब में गयी इसी रकम में से वह समय-समय पर राजनीतिक दलों को चंदे व स्थानीय टपोरियों आदि पर खर्च करता है।

चुनाव की इस बेला में जनता को बहकाने व रैलियों में आकर्षित करने के लिये सभी नेतागण, चाहे कांग्रेसी हों या भाजपाई इस तरह के शगूफ़े छोड़ते रहते हैं। यह जनता की ज़िम्मेवारी है कि वह लच्छेदार भाषणों में बहने की अपेक्षा इन शगूफ़ों की तह में जाकर इनको अच्छी तरह से समझे व बहस करे, वरना फिर बरसों तक पछताना पड़ेगा।

पुलिस संरक्षण में चलता देह व्यापार व जुआ

फ़रीदाबाद (म.मो.) पुलिस कमिश्नर उनके डी.सी. पी, ए सी पी की फ़ौज शहर में राई बराबर अपराध पर लगाम तक नहीं लगा पाये। जिसके चलते अपराधी आये दिन शहर में आसानी से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देकर पुलिस कमिश्नर के मुंह पर कालिख पोत रहे हैं। शहर में हत्या, लूट-पाट, अपहरण, जुआ, सट्टा, शराब तस्करी, देह-व्यापार का धंधा जमकर चल रहा है

देह व्यापार का धंधा करने वाले दलालों के अपने धंधे का ट्रेंड बदलते हुए धंधे को मसाज पार्लर का नाम दिया है। शहर में जगह-जगह खुले मसाज पार्लरों में देह-व्यापार के धंधे में नाबालिग लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर धंधे में लगाया जा रहा है। मसाज पार्लरों की आड़ में जिस्म का धंधा खुलकर करवाया जा रहा है।

मथुरा रोड स्थित मैनहट्टन मॉल में पहली मंजिल पर लक्की सरदार जवाहर कॉलोनी निवासी मसाज पार्लर की आड़ में धड़ल्ले से नाबालिग लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवा रहा है। सूत्रों के अनुसार फ़रीदाबाद में मसाज पार्लरों को खुलवाने वाला ही लक्की सरदार है। जो कि पिछले कुछ समय में ही कई वेश्यावृत्ति के अड्डों का मालिक बना बैठा है।

वहीं पहली मंजील पर उसने एक किसिंग सेंटर भी खोल रखा है। इस किसिंग सेंटर में छः कैबिन बने हुए हैं। जिसके अंदर सिर्फ स्कूली छात्र-छात्राओं को कुर्कम करने की छूट देते है। जिसके एवज में 400 रुपया प्रति घंटा वसूलते हैं। लक्की सरदार रोजाना नई लड़कियों का प्रबंध दिल्ली, सिलीगुड़ी व अन्य प्रदेशों में बैठे दलालों से करता है।

एसा नहीं है। कि लक्की सरदार धंधे की कमाई या दलाली अकेले डकार जाता है। बल्कि उस दलाली का एक मोटा हिस्सा पुलिस के उच्चाधिकारी तक भी पहुंचवाता है। जिसके चलते बेखौफ़ होकर लक्की सरदार वेश्यावृत्ति का धंधा मसाज पार्लरों में खुलकर करवा रहा है। लक्की को यह कहते भी सुना गया है कि पुलिस धंधे की कमाई में से अपना हिस्सा तो बड़ी बेशर्मी के साथ लेती है। वही दूसरी तरफ़ हर दूसरे दिन मसाज पार्लर की सेवाएं भी लेती है

मामले की पुष्टि करने के लिये इस संवाददाता ने वहां छिप कर कुछ दिन निगरानी करने पर पाया कि सेक्टर 16 का चौकी इन्चार्ज व पी सी आर जिप्सी पर तैनात पुलिसकर्मी दिनांक 27 व 28 जुलाई 12, 14,व 15 अगस्त को यहां आकर 'मसाज' आदि की सेवा भी करा गये चलते हुए काली कमाई में से अपना हिस्सा भी ले गये इसके अलावा जिन-जिन पुलिसकर्मियों को इस ठिकाने का पता है वे भी नियमित रूप से यहां चक्कर लगाते रहते हैं, खासकर सी आई ए वाले।

वहीं दूसरी तरफ़ ऑन लाइन कैसिनो संचालक पुलिस आशीर्वाद के चलते पुन: कैसिनो सेंटर खोलकर स्कूली छात्रों व युवाओं को बर्बाद करने पर लग गए हैं। इसी साल 2 नम्बर में हिमांशु ऑनलाईन कैसिनो संचालकों से मोटे व्याज पर रकम लेकर कैसिनो में हार गया था। जिसके चलते उसने 26 फरवरी को ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या कर ली थी।

हिमांशु की आत्महत्या के लिये परिजनों ने पवन सुखदयाल धर्मपाल, मनोज भाटिया को जिम्मेवार माना था। 'हिमांशु' आत्महत्या पर पनपे जनाक्रोश के चलते हिमांशु के परिजनों व ब्लॉक वासियों ने हार्डवेयर चौक जाम कर मोमबत्ती जूलूस निकाला था। पुलिस के उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला काबू में आया था वो कैसिनो सेंटर तो बंद हो गया लेकिन वही काम अब एस जी एम नगर थाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा जोर-शोर से चालू है। जब फ़िर कोई नई वारदात होगी। तो एक बार फ़िर पुलिस कार्यवाही का ड्रामा करके जनता को शांत करा दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार एस जी एम नगर थाना प्रभारी प्रत्येक सेंटर संचालक से 15-20 हजार रुपया महीना ले रही है। ऑन लाईन कैसिनो के धंधे को मुख्य रूप से सुखदयाल, धर्मपाल, मनोज भाटिया, मनोज जनता कॉलोनी, बिल्डर अजय कथूरिया, गुलशन भाटिया राकेश चक्की वाला, रचित आशीष खत्री (5 नं.) खुलेआम कर रहे हैं।

शिवचरण टटोल रहे हैं मुनाफ़ा कहां मिलेगा ?

फ़रीदाबाद (म.मो.) पंडित शिवचरण लाल शर्मा, इस नाम से शहर का शायद ही कोई शख्स वाकिफ न हो। कुछ साल पहले तक एक आम आदमी की तरह रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले और अपना व अपने परिवार का पेट पालने के लिए तरह तरह के धंधे करने वाला शिवचरण अब शहर का प्रमुख धन्ना सेठ बन चुका है। शिवचरण की राजनीति की दुकान कुछ इस तरह चली कि वह अब मुख्यमंत्री तक को आंख दिखाने से भी बाज नहीं आता। शहर का शायद ही कोई सरकारी काम हो, जिसमें शिवचरण की हिस्सेदारी न हो। नगर निगम के सारे ठेकेदार शिवचरण के तलुवे चाटने को मजबूर हैं और अधिकारी शिवचरण की ड्योढी पर खड़े रहते हैं। हालात यह हैं कि अपनी कमाई में हिस्सेदारी न देने पर शिवचरण ने पिछले दिनों नगर निगम ने एक एक्सईएन का ट्रांसफर करा दिया, हालांकि एक्सईएन भी घाघ है और अभी तक शहर में ही जमा हुआ है।

एनआइटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक शिवचरण इस बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसने उस कांग्रेस पार्टी से टिकट का आवेदन तक नहीं किया, जिस पार्टी ने उसे पूरे पांच साल तक पाला पोसा और जिससे उसने जन्मजात रिश्ता बताया था। कांग्रेस ने सियासी मजबूरी के चलते उसे पहली बार में ही मंत्री बना दिया और उसे फरीदाबाद और गुड़गांव में हर तरह की लूट की छूट दी। मामला चाहे चेंज आफ लैंड यूज (सीएलयू) का हो या उद्योगों में दलाली का हो या विकास कार्यों पर खर्च हो रही रकम में हिस्सेदारी का, मंत्री शिवचरण को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर तरह की छूट दी, लेकिन जब हुड्डा का जहाज डूबने को आया तो भागने वालों में शिवचरण भी शामिल हो गया। वह शहर में जो भी प्रचार कर रहे हैं, उसमें कहीं कांग्रेस का नामोंनिशान नहीं है, न ही हुड्डा का फोटो।

शिवचरण प्रचार कर रहा है कि वह फिर से निर्दलीय लड़ेगा, लेकिन अंदरखाने वह भाजपा की टिकट लेने की जुगत में है। पिछले लोकसभा चुनाव में कार्पोरेट की मदद से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्या बना कि कई दलबदलू नेताओं को लगता है कि हरियाणा में भी भाजपा की हवा चलेगी। शिवचरण भी ऐसे दलबदलू नेताओं की सूची में शामिल है और भाजपा की गोद में जाने को बेताब है। उसके नजदीकी बताते हैं कि भाजपा के साथ जाने के पीछे एक

शेष पेज पांच पर